22 दिसम्बर, 2016,

प्रेस–विज्ञप्ति

निर्धन हो या धनवान, सबको शिक्षा एक समान!!

लोकतंत्र को बचाना है तो सरकारी स्कूल बचाना होगा : अम्बरीश राय, संयोजक, आरटीई फोरम

लखनऊ, 21–22 दिसम्बर २०१६ को संपन्न आर० टी० ई० फोरम की राष्ट्रीय परिषद् की बैठक में देश भर के तकरीबन 14 राज्यों से आरटीई फोरम के प्रतिनिधियों व विभिन्न नागरिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों समेत विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया।

राइट टू एजुकेशन फोरम (आरटीई फोरम) एक राष्ट्रीय मंच है, जिसका गठन राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी) की सामूहिक पहल के जरिये हुआ था। राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर कार्यरत शिक्षा मंचों व नेटवर्कों, शिक्षक संगठनों, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत देश के मुख्तलिफ हिस्सों में शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे तकरीबन दस हजार ग्रास–रूट संगठनों के साझा राष्ट्रीय मंच के बतौर आरटीई फोरम देश भर की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में सार्थक बदलाव के लिए प्रयासरत है।

राष्ट्रीय परिषद की इस इस दो दिवसीय अर्द्धवार्षिक बैठक में शिक्षा से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों पर गंभीर चिंतन–मनन किया गया तथा आर० टी० ई० फोरम कि आगामी वर्ष के लिए मुद्दों को चिन्हित करते हुए भावी कार्य योजना तैयार की गई। विभिन्न राज्यों से आए हुए प्रतिनिधियों ने अपने राज्य–केंद्रित स्कूली शिक्षा की समस्याओं को साझा किया। विभिन्न सत्रों में स्कूली शिक्षा के निजीकरण, शिक्षकों की भारी कमी, बजट में लगातार कटौती के कारण कानून के कार्यान्वयन में आ रही दिक्कतों, केंद्र सरकार द्वारा लाई जा रही नई शिक्षा नीति, आउट आफ स्कूल बच्चों की समस्या एवं बच्चों के लिए सुरक्षित स्कूलों की गारंटी करने पर चर्चा हुई।

अपनी भावी रणनीति के लिए परिषद द्वारा ये फैसले लिए लिए गए –

1. केंद्र सरकार द्वारा बनाई जा रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आरटीई एक्ट के कार्यान्वयन की गहरी अनदेखी है जो एक बडी चिंता का विषय है। ऐसी किसी भी नीति का फोकस शिक्षा के मौलिक अधिकार पर होना चाहिए। आरटीई फोरम एक ऐसी समावेशी शिक्षा नीति बनाने पर जोर देगा और उसके लिए देशव्यापी अभियान चलाएगा जो संवैधानिक मूल्यों पर आधारित हो।
2. वर्तमान केंद्र सरकार ने सत्ता में आने से पहले अपने चुनावी घोषणापत्र में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का न्यूनतम 6% शिक्षा पर खर्च करने का वादा किया था। लेकिन पिछले बजटों में हुई लगातार कटौती ने शिक्षा के क्षेत्र को और भी खस्ताहाल कर दिया है। फिलहाल सरकार महज 3.8 फीसदी खर्च कर रही है जिसका 90 फीसदी हिस्सा 'सेस' से आ रहा है जिसका लक्ष्य दरअसल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी के लिए मौजूद कमियों को पूरा करना था। शिक्षा अधिकार कानून के प्रति सरकार के ढुलमुल रवैये के खिलाफ आरटीई फोरम केंद्र सरकार से मांग करता है की सरकार संसाधनों की कमी का रोना छोडकर अपना वायदा पूरा करे।

3. शिक्षा अधिकार कानून २००६ का दायरा बढ़ा कर पूर्व प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को इसमें शामिल किया जाए।
4. सभी स्कूलों में शिक्षा अधिकार अधिनियम २००६ को लागू करने की कानून में दी गयी दोनों समयावधि सम्माप्त हो चुकी है,। इसलिए इसके लिए नई समयसीमा एवं नई कार्ययोजना लाई जाए। इसके लिए जनदबाव बनाने हेतु आरटीई फोरम अपनी राज्य इकाइयों के जरिये पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाएगा।
5. पीपीपी, वाउचर सिस्टम एवं शिक्षा के क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे ब्रिज इंटरनेशनल, पीयर्सन जैसी अंतरराष्टीय निजी कंपनियों के हाथों में शिक्षा को सौंपने समेत शिक्षा में किसी भी प्रकार के निजीकरण का आरटीई फोरम विरोध करता है और इसके लिए वह देशव्यापी अभियान चलाएगा। साथ ही, यह निजी विद्यालयों को कानूनी दायरे में लाकर उनके लिए एक नियामक ढांचे की मांग करता है।
6. आरटीई एक्ट के पूर्ण कार्यान्वयन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी के लिए फोरम हर स्तर पर पैरवी करेगा।
7. स्कूल प्रबंधन समिति को प्रभावी एवं क्रियाशील बनाने के लिए वह एसएमसी फेडरेशंस का गठन करते हुए पूरे देश में काम करेगा।
8. देश के विभिन्न राज्यों में होनेवाले विधान सभा चुनावों में शिक्षा को राजनीतिक मुद्दा बनाने में और इसे उनके चुनावी घोषणापत्र में प्राथमिकता दिलाने के लिए फोरम जनअभियान चलाएगा खासकर उत्तर प्रदेश में अपनी राज्य इकाई, स्कोर व एसएमसी फोरम के साथ मिलकर ....

- सभी राजनीतिक पार्टियों से संपर्क कर उनके घोषणापत्र में शिक्षा को प्राथमिकता दिलाने का प्रयास करेगा !
- सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपने मांगपत्र के माध्यम से चुनाव प्रत्यशियों के साथ संवाद कायम कर शिक्षा के संदर्भ में उनकी सोच–समझ बनाने और शिक्षा पर प्रतिबद्धता के साथ काम करने का वायदा लेने का काम करेगा।
- शिक्षा चुनाव का प्रमुख एजेंडा बने इसके लिए जनता के सभी तबके के लोगो , उनके संगठनो से संवाद कायम करेंगे और मिल कर एक जन अभियान चलाएंगे
- शिक्षा को व्यापक जनांदोलन का मुद्दा बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मलेन गोष्ठी एवं व्यापक प्रचार–प्रसार करेंगे !

धन्यवाद,

अम्बरीष राय, राष्ट्रीय संयोजक, आरटीई फोरम
मित्ररंजन, मीडिया समन्वयक, आरटीई फोरम

प्रशांत प्रकाश, बिनोद सिन्हा संयोजक, स्टेट कलेक्टिव राइट टू एजुकेशन (स्कोर)
संपर्क: **9721663322/8687955444**
अजय शर्मा, **9415868533**